this year is going to be celebrated as the year of shelter for the human beings.?

SHRI J. VENGAL RAO: This R&D unit every industry has got. We have appointed an expert committee under Dr. Visveswarayya. He has submitted the report in the last week of March. It is under consideration and we are seeing how to rectify all these defects.

SHRI B. L. PANWAR: When it has reached a saturation point the present...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Industry has reached the saturation point. What do you want to ask?

SHRI B. L. PANWAR: In view of the limited R&D being available in the country, what is the Government doing with regard to the cement industry?

SHRI J. VENGAL RAO: That is why I mentioned that we have appointed a high level committee of experts to find out how to further develop the R&D in this industry. This committee has been appointed under the chairmanship of Dr. Visveswarayya. He has suggested so many methods. It is under the consideration of the Government?

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Madam, power cut applies both to the private sector and the public sector. When the private sector cement companies are making huge profits, what are the reasons then for the units of the Cement Corporation of India to go into losses. Another thing, Madam, the Minister being a Union Minister is talking about Andhra Pradesh only. But the question relates to the entire country. Probably the Minister may be suffering from the NTR syndrome. That is why he is talking about Andhra Pradesh.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, that is not the question.

SHRI J. VENGAL RAO: He is mistaken, because I said that the installed capacity of the Cement Corporation of India, to the extent of 50 per cent, is in Andhra Pradesh. We are extending all help to Andhra Pradesh. At my request only, the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra are supplying 400 MW of power to Andhra Pradesh; his Chief Minister knows it very well.

*202. [*Transferred to the 10th May, 1988.*]

*203. [*The questioner (Shri Yalla Sesi Bhushana Rao) was absent. For answer,* vide col. 36—38 infra.]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के बाटलिंग संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

*204. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों के निवासियों को रसोई गैस की आपूर्ति में पेश आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए, वाराणसी/आजमगढ़ अथवा गोरखपुर में रसोई गैस का एक बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के मसौदे का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आएगा ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1986 और 1987 के वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में रसोई गैस की कितनी-कितनी खपत हुई और 1988 के वर्ष के दौरान इसकी अनुमानत: कितनी खपत होगी ;

(घ) खपत के अनुपात में गैस की नियमित आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) कितने व्यक्तियों ने विभिन्न गैस डीलरों/एजेंटों के यहां अपने नाम दर्ज कराये हैं और अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(च) उन्हें कब तक गैस कनैक्शन दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में मुख्य कठिनाईयां क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) वाराणसी और गोरखपुर में निम्नलिखित चार एल०पी०जी० बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं :

स्थान	क्षमता (एम टी पी ए)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	शुरु करने की संभावित तिथि
वाराणसी . . .	25000	11.77	मार्च, 1989
गोरखपुर . . .	5000	3.25	मार्च, 1989

(ग) विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	एल० पी० जी० की खपत मी. टन
1986	20414
1987	27438
1988 (अनुमानित)	33100

(घ) देश में एल०पी०जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा यथासंभव आयात के द्वारा भी इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त इसकी बाटलिंग तथा वितरण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को एल०पी० जी० की नियमित सप्लाई सुनिश्चित" करने के लिए तेल उद्योग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

(ङ) 1 अप्रैल, 1988 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए लगभग 1.19 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(च) पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तेल उद्योग द्वारा अपने उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से एल०पी०जी० कनेक्शन जारी किए जाते रहेंगे, बशर्ते कि एल०पी०जी० उपलब्धता और बाटलिंग क्षमता में वृद्धि हो।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि वाराणसी और गोरखपुर में बाटलिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा कि उत्तर में आया है कनैक्शनों के लिए लगभग 1 लाख 19 हजार लोग प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं और निरन्तर उसमें वृद्धि होती जा रही है। अतः उसकी आवश्यकता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आजमगढ़ में भी बाटलिंग प्लांट लगाने का प्रयास करेंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इस समय पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी आवश्यकता है और कितनी खपत है? और जो शेष बच जाता है उसकी पूर्ति माननीय मंत्री जी कैसे करेंगे। कितना वे और इंपोर्ट करने जा रहे हैं?

उपसभापति : यह आपने सवाल किया है ईस्टर्न यू० पी० का और सवाल पूरे देश का कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसा कि उत्तर में आया है, में 1 लाख 19 हजार कनेक्शनों के लिए रजिस्टर्ड हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए और जो अभी रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए क्या आजमगढ़ जैसे

में भी एक बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का प्रयास माननीय मंत्री जी करेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि इस समय देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी आवश्यकता है और कितनी खपत है और जो शेष है उसकी पूर्ति माननीय मंत्री जी किस प्रकार कर रहे हैं और कितना उसके लिए इंपोर्ट किया जा रहा है ?

SHRI BRAHM DUTT: We are in the third phase of expansion of bottling capacity in our country. I have already submitted, the third phase is the Varanasi and Gorakhpur plants. Besides, five other plants in U.P. are proposed, and we will try and we expect that their commissioning will be in 1989. But we are also considering fourth phase of bottling capacity.

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौथे फेज में जरूर आएगा और यह जो तैकलॉग है। 1 लाख 19 हजार का यह पूरे देश को देखते हुए बहुत कम है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया है पूरी एल०पी०जी० की उपलब्धता के बारे में। तो 1987–88 में हमारी 1590 मीट्रिक टन उपलब्धि थी देश के अन्दर और 155 हजार टन हमने इम्पोर्ट किया। इस तरह से कुल उपलब्धि 1745 की है जो हमारी आवश्यकता को लगभग पूरा करता है।

श्री राम नरेश यादव : क्या आप, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जब अगला कदम उठाएंगे तो उस सिलसिले में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में और किसी स्थान के बारे में विचार करेंगे। उसमें मेरा आग्रह है कि आजमगढ़ के बारे में अवश्य विचार करें और उस संबंध में अभी से सर्वे कराने का आरम्भ क्या करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय, मैं तो सर्वे उसका करा ही रहा हूं और आजमगढ़ का भी जरूर ध्यान रखा जाएगा और आजमगढ़ में भी अगर कोई विशेष स्थान हो तो उसका भी ध्यान अवश्य रखा जाएगा, देखना यह पड़ेगा कि वहां तक पहुंचने का साधन उपलब्ध हो।

श्री राम नरेश यादव : अकेले आजमगढ़ के माननीय, सात एम०पी० हैं, 14 एम० एल० ए० है इसलिए उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय, बाटलिंग प्लांट की स्थापना माननीय संसद सदस्यों की संख्या के हिसाब से नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे तो फिर ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा जरूरत है, लेह और कारगिल में, बेचारे एक एम० पी० हैं तो वहां तो कुछ होगा ही नहीं। वहां का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग आवश्यकता आपकी पूरी करेंगे।

श्री शांति त्यागी : मैडम, एक छोटी सी जानकारी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यू० पी० में फ्रीडम फाइटर के नाम पर कितनी एल० पी० जी० कनेक्शन एजेंसी आवंटित है।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय, इसके लिए तो मैं सूचना प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

SHRI KAPIL VERMA: Madam, Deputy Chairman, the distribution and supply of cylinders by the local agencies in Eastern U.P. is highly unsatisfactory. As the hon. Minister knows, I come from Eastern U.P. and I know some of these agencies are functioning erratically. There is the example of my own district, Jaunpur, which has a very big population. But there is a litigation going on between two agencies with the result that the cylinders are not made available locally regularly and they have to be brought from Varanasi This naturally causes disruption in supply. I would, therefore, like to know, what arrangements are going to be made to ensure that the people of Eastern U.P. who have gas connections—of course, there are more

than one lakh people on the waiting list, waiting for gas connections—get their supplies regularly in view of the fact that the functioning by these agencies is very erratic. What steps the hon. Minister is going to take in this regard?

SHRI BRAHM DUTT: Madam, there are some problems. The hon. Member gave the example of Jaunpur where a litigation is going on. What we generally do is that we allot the agency temporarily to the Essential Commodities Corporation or to the Division or the Mandal Vikas Nigam. But in regard to the instance pointed out by the hon. Member, I will enquire into it and find out the position in the case of Jaunpur. I will try to make adequate arrangements.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Madam, an important element of a bottling plant are the cylinders themselves. Is the Government aware of the fact that at a time when there is no authorised plant for manufacture of LPG cylinders in Eastern U.P., there are quite a few unauthorised units manufacturing spurious cylinders and making use of them with the help of the concerned authorities? I would like to know from the hon. Minister what steps he proposes to take to prevent the manufacture and supply of spurious cylinders.

SHRI BRAHM DUTT: Madam, the manufacture of cylinders is in the small-scale industry. According to my information, no licence is required. When the oil companies purchase, they purchase from the units who manufacture the cylinders according to the standard laid down. The ISI mark should be there. We take all precautions. But the possibility of presence of spurious cyinders in the market cannot be ruled out. We generally conduct raids and so on. Whenever complaints are received, they are promptly attended to. We are making our best efforts. But I am not saying that a certain quantity of spurious cylinders is not there in the market.

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति महोदय, आपके द्वारा तेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री राम नरेश यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रश्न की पृष्ठभूमि में बजा आजमगढ़ के सारे उत्तर प्रदेश के हित को दृष्टिगत रखते हुए किस तरह का आपका प्रस्ताव है बोटलिंग का एल० पी० जी० प्लांट लगाने के लिए ? आप सारे प्रांत के संबंध में बात सोच रहे हैं या किसी विशेष जिले के संबंध में सोच रहे हैं ? मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश के हित को दृष्टि में रखते हुए किसी विशेष जिले में बोटलिंग का एल० पी० जी० का प्लांट लगायेंगे या केवल एक ही जिले के हित को दृष्टिगत रखकर लगायेंगे यही मैं आप से जानना चाहता हूं ?

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय केसरी जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया । उनका तो सुझाव भी मेरे लिए आदेश के माफिक है । अगर आप देखें तो हमारे वर्तमान बोटलिंग प्लांट कानपुर में, मथुरा में, इलाहाबाद में और बरेली में हैं । पिछले वर्ष कुछ नये बोटलिंग के प्लांट लगाने की कोशिश की हैं । तर्क संगत रूप से एक हमने कानपुर में लगाया । उससे मध्य उत्तर प्रदेश के भाग की आवश्यकता पूरी होगी । दूसरा हल्द्वानी में लगाया है इससे कमाऊं की आवश्यकता पूरी होगी । तीसरा वाराणसी में लगाया ताकि उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो । वाराणसी में जो लगाया है उसकी 25 हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी है । एक हरिद्वार में प्रस्तावित है । जमीन की दिक्कत हो रही है । एक लखनऊ में छोटा प्लांट प्रस्तावित है । गोरखपुर में प्रस्तावित है । जहां-जहां आवश्यकता होगी वहां हम लगायेंगे । मैंने चतुर्थ चरण के लिये सर्वे करा लिया है । हम चाहते है जहां नहीं है उन क्षेत्रों में हम लगाएं ताकि एल०पी०जी० सिलेंडरों को ले जाने में दिक्कत न हो । मापदंड यह होगा कि कितनी दूर एल० पी० जी० सिलेंडर ले जाने हैं ।